प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

04.04.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

'' मुख्य समाचार''

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होने को पारदर्शी व समावेशी विकास में बताया ऐतिहासिक कदम।
- राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरंभ करने को दी मंजूरी।
- केंद्र सरकार की ग्रामीण पेयजल सुधार व आजीविका परियोजना के तहत प्रदेश के दस जिलों के 6 लाख से अधिक लोगों को जलापूर्ति व स्वच्छ सेवाएं देने का प्रावधान।

- कांगड़ा जिले में वर्ष 1905 में आए भूकंप की वर्षगांठ पर प्रदेश में आपदा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

वक्फ संशोधन विधेयक

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक–आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं अन्य लोगों सहित गरीब वर्ग को लाभ होगा। इससे पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में वक्फ–संशोधन–विधेयक पर 17 घंटे और 2 मिनट तक चर्चा की गई और इस रिकॉर्ड को तोड़ना बेहद मुश्किल लगता है। किरेन रिजिजू ने कहा कि सबसे पहले वक़्फ़ बिल में पुराना रिकॉर्ड 1981 में 16 घंटे 51 मिनट एसमा अधिनियम पर रिकॉर्ड चर्चा की गई थी और राज्य सभा में कल 17 घंटे 2 मिनट तक चर्चा की गई जो एक एक रिकॉर्ड बन गया।

वक्फ संशोधन विधेयक–2

इधर प्रदेश में भी वक्फ संशोधन विधेयक–2025 का लोगों ने स्वागत किया है। उन्होंने संशोधन को वक्त की ज़रूरत बताते हुए कहा कि इस विधेयक में संशोधन होने के बाद वक्फ की मनमानी पर रोक लगेगी और पारदर्शिता आयेगी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।

मुख्यमंत्री

राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर शुरू की गई इस योजना के तहत हर वर्ष पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस पर 6 श्रेणियों में कुल दस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने शिक्षा, संस्थान विकास, मेंटरशिप, सामाजिक आउटरीच, अनुसंधान व नवाचार के क्षेत्र में योगदान से छात्रों के विकास व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ये पुरस्कार किसी भी शिक्षक को उनके पूरे सेवाकाल के दौरान केवल एक बार ही दिया जाएगा।

बैठक

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अध्यक्षता में आज चंबा में जिला योजना विकास एवं 20 सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गैर सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न योजनाओं

के लिए जारी किए गए बजट का सही सदुपयोग कर विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

वीरन्ना सोमन्ना

केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वीरन्ना सोमन्ना ने ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के 6 लाख 20 हजार लोगों को ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छ सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है। लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के सवाल के जवाब में उन्होंने संसद में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के ऋण की अंतिम तिथि 30 जून 2028 है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से चल रही ग्रामीण पेयजल योजना को अपग्रेड किया जाएगा। राजीव भारद्वाज के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय नवीन व नवीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने बताया कि हिमाचल की सभी पंचायतों में मुफ्त सौलर रूफटॉप पॉवर प्लांट लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं

जागरूकता दिवस

प्रदेश के कांगड़ा जिले में 4 अप्रैल 1905 को आए विनाशकारी भूकंप की 120वीं वर्षगांठ को आज राज्य में आपदा जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया गया। 7 दशमलव 8 तीव्रता के इस भीषण भूकंप में लगभग 20 हजार लोगों ने जान गंवाई थी और लगभग एक लाख घर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इस उपलक्ष्य पर शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आज मॉकड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें अग्निशमन विभाग, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग आपदा के प्रति जागरूक हो सकें। मुख्य सचिव ने भूकंपरोधी भवन निर्माण पद्धतियों को अपनाने पर भी बल दिया। इससे पहले आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक व विशेष सचिव डी. सी राणा ने कहा कि आपदा जागरूकता के लिए सभी जिला मुख्यालयों में आज नागरिक एकजुटता मार्च निकाला गया और 5 अप्रैल तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्रों से जुड़ी गतिविधियां करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों को अप्रैल माह के लिए ग्राम सभा के एजेंडे में आपदा के लिए तैयारी और जागरूकता को शामिल किया गया है।

भ्रष्टाचार मुहिम

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई शिमला के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में आगे आने का आह्वान किया है। आकाशवाणी शिमला से विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से ही भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में सफलता हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोग बिना किसी डर के सीबीआई के कार्यालय में आकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और शिकायत के लिए कार्यालय के ई–मेल और दूरभाष नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है।

कांग्रेस प्रदर्शन

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के नज़दीक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता जानबूझकर बेवजह मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार को निशाना बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ सांसद हैं और अनुराग ठाकुर सदन में अभद्र टिप्पणी करके जानबूझकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनीयर महाप्रबंधन विमल नेगी की मृत्यु मामले में आए दिन प्रबंधन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं फिर भी सरकार सीबीआई जांच से भाग रही है। मंडी से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि जिस तरह से पावर कॉपोरेशन से जुड़े लोग पेखुबेला और शौंगटौंग करछम जलविद्युत परियोजना को लेकर आरोप लगा रहे हैं, वे बेहद दुख व शर्मनाक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बाद भी सरकार इस मामले की निष्पक्षता से जांच करवाने के बजाय इन आरोपों पर पर्दा डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने अस्पतालों में ओपीडी के मरीजों की निशुल्क जांच की सुविधा बंद करने और ओपीडी के पंजीकरण के लिए शुल्क लेने संबंधी निर्णय पर सरकार से अपना रूख स्पष्ट करने को कहा है।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होने को पारदर्शी व समावेशी विकास में बताया ऐतिहासिक कदम।
- राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विशिष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य पुरस्कार योजना आरंभ करने को दी मंजूरी।
- केंद्र सरकार की ग्रामीण पेयजल सुधार व आजीविका परियोजना के तहत प्रदेश के दस जिलों के 6 लाख से अधिक लोगों को जलापूर्ति व स्वच्छ सेवाएं देने का प्रावधान।
- कांगड़ा जिले में वर्ष 1905 में आए भूकंप की वर्षगांठ पर प्रदेश में आपदा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।